नईदुनिया

खास-खबरें

वैंस इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: इंडियन रेल, मेट्रो और रिन्यूएबल इनर्जी सिस्टम्स के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) बनाने वाली कंपनी वैंस इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग लिमिटेड का 33.98 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में एक अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद पांच अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि छह अक्टूबर को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर सात अक्टूबर को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद शाम 3:30 बजे तक यह आईपीओ 2.04 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 112 रुपये से लेकर 118 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,200 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 2,400 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,83,200 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 28.80 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं।

नई सेडान में मिलेंगे अपडेटेड फीचर्स जल्द भारतीय बाजार में होगी लॉन्च

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल कंपनी स्कोडा भारतीय बाजार में अपनी नई सेडान कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी लोकप्रिय सेडान स्लाविया के फेसलिफ्ट मॉडल को पेश करने वाली है। नए मॉडल को कई अपडेटेड फीचर्स और डिजाइन बदलावों के साथ बाजार में उतारा जा सकता है। इस कार की बुकिंग कुछ डीलरशिप पर 15 हजार रुपये की शुरुआती राशि में शुरू होने की जानकारी सामने आई है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को कंपनी मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा आधुनिक लुक और बेहतर सुविधाओं के साथ पेश कर सकती है। नई कार में एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव के साथ नए फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है। कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेडान सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नई स्लाविया में इंटीरियर को भी अपडेट किया जा सकता है।

सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च हुआ एवरेस्ट आईएमएस का पब्लिक इश्यू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: आईटी सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी एवरेस्ट आईएमएस टेक्नोलॉजीज का 48.46 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में पांच अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद छह अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि सात अक्टूबर को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर आठ अक्टूबर को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद पहले दिन के अंत तक यह आईपीओ 13 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 80 रुपये से लेकर 85 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,600 शेयर का है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा को लेकर लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म

एआई एजेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच कंपनियों के लिए सुरक्षा कवच तैयार करेगा नया सिस्टम

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने एआई एजेंट्स की सुरक्षा के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कंपनी ने ओपनशेल सेंट्री नाम से एक सुरक्षा प्रणाली पेश की है, जिसका उद्देश्य एआई एजेंट्स की गतिविधियों पर नजर रखना और संभावित खतरों से बचाव करना है।

एआई एजेंट्स ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो इंसानों की तरह निर्णय लेने, जानकारी जुटाने और कई कार्यों को अपने स्तर पर पूरा करने में सक्षम होते हैं। इनका इस्तेमाल कंपनियों में ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण, सॉफ्टवेयर विकास और अन्य व्यावसायिक कामों के लिए तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, इनकी बढ़ती क्षमताओं के साथ इनके गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिमों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

एनवीडिया के अनुसार, ओपनशेल सेंट्री प्लेटफॉर्म कंपनियों को एआई एजेंट्स की निगरानी और सुरक्षा में मदद करेगा। यह सिस्टम एआई एजेंट्स की गतिविधियों को ट्रैक करने, असामान्य व्यवहार की पहचान करने और संभावित जोखिमों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि एआई सिस्टम के अधिक स्वायत्त होने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी हो गया है।

एआई क्षेत्र में कई कंपनियां नए मॉडल और एजेंट आधारित तकनीक विकसित कर रही हैं। इन तकनीकों के जरिए एआई सिस्टम को अधिक स्वतंत्र तरीके से काम करने की क्षमता मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सिस्टम के इस्तेमाल में डेटा सुरक्षा, गलत निर्णय और अनधिकृत पहुंच जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। एनवीडिया का नया प्लेटफॉर्म इसी तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह कंपनियों को अपने एआई सिस्टम पर बेहतर नियंत्रण रखने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने में सहायता देगा। एनवीडिया लंबे समय से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रही है और उसके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) एआई मॉडल के प्रशिक्षण और संचालन में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी अब एआई हार्डवेयर के साथ-साथ सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े समाधान विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। एआई तकनीक के विस्तार के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दुनिया भर में चर्चा बढ़ रही है। ऐसे में एनवीडिया का यह नया सुरक्षा प्लेटफॉर्म कंपनियों को एआई एजेंट्स के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में कदम माना जा रहा है।

शेयर बाजार में लगातार आठवें दिन गिरावट, सेंसेक्स 243 अंक फिसला

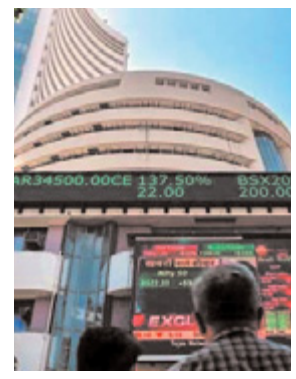

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार आठवें दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 243 अंक टूटकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 64 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर आ गया। बाजार में ऑटो, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी और रियल्टी शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समझौते की संभावना नहीं दिखने से निवेशकों की चिंता बनी हुई है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव का असर भी बाजार के माहौल पर पड़ा है। इन अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण निवेशकों में सतर्कता बढ़ी और प्रमुख सूचकांकों पर दबाव बना रहा।

एशियाई बाजारों में भी मंगलवार को गिरावट रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 19 अंक गिरकर 6,871, जापान का निक्केई 396 अंक टूटकर 65,481 और हांगकांग का हैंगसेंग 119 अंक की गिरावट के साथ 24,524 पर बंद हुआ। इससे पहले 28 सितंबर को अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई थी। डाउ जोंस 347 अंक, नैस्डैक 248 अंक और एसएंडपी 500 में 60 अंक की गिरावट रही।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी बाजार पर दबाव बढ़ा रही है। पिछले सात दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,353 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। इसी अवधि में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,189 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। पिछले 30 दिनों में विदेशी निवेशकों की शुद्ध बिकवाली 12,457 करोड़ रुपये रही, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 14,670 करोड़ रुपये की खरीदारी की। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 1,124 अंक गिरकर 72,772 और निफ्टी 360 अंक टूटकर 22,780 पर बंद हुआ था।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की तैयारी एक नवंबर से लागू होंगे सख्त नियम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए 1 नवंबर से कई सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं। प्रस्तावित योजना में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की एंट्री सीमित करने और पार्किंग व्यवस्था में बदलाव जैसे कदम शामिल हैं।

दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। बीएस-6 मानकों वाले वाहनों के संचालन को प्राथमिकता देने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना है।

प्रस्तावित नियमों के तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों की संख्या कम करने के लिए प्रवेश प्रतिबंधों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में निजी वाहनों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने जैसे उपाय भी लागू किए जा

बीएस-6 मानकों वाले वाहनों को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी

सकते हैं। इससे लोगों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी।

सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसके पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण गतिविधियां, पराली जलाना और मौसम संबंधी परिस्थितियां प्रमुख कारणों में शामिल हैं। हर साल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से अलग-अलग उपाय किए जाते हैं।

नई योजना के तहत वाहनों की जांच, प्रदूषण प्रमाण पत्र और यातायात नियमों के पालन पर भी निगरानी बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी विभागों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार कर रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार इस बार सर्दियों से पहले ही तैयारियां शुरू कर रही है। 1 नवंबर से लागू होने वाले संभावित नियमों का उद्देश्य राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

मेटा ने भारतीय मूल के सीजे देसाई को सौंपी एआई की कमान

मार्क जकरबर्ग को सीधे रिपोर्ट करेंगे, एंटरप्राइज एआई कारोबार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: मेटा ने भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ चिरंतन 'सीजे' देसाई को कंपनी के नए एंटरप्राइज एआई कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी है। देसाई मेटा में चीफ एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म ऑफिसर के पद पर काम करेंगे और सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग को रिपोर्ट करेंगे। कंपनी ने मेटा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसके जरिए कारोबारियों और डेवलपर्स को कंपनी की एआई तकनीक, मॉडल, एजेंट और अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

देसाई इससे पहले डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी मोंगोडीबी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने नवंबर 2025 में यह जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वे क्लाउडफ्लेयर में उत्पाद और इंजीनियरिंग के अध्यक्ष तथा सर्विसनाउ में कई वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। उनके तकनीकी करियर की शुरुआत 1995 में ओरेकल से हुई थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना-शैंपेन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री और

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया है। मेटा के अनुसार, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म का शुरुआती फोकस कंपनी की एआई तकनीक को कारोबारियों और डेवलपर्स तक पहुंचाने पर होगा। इसमें म्यूज़ एआई एजेंट, मेटा बिजनेस एजेंट, म्यूज़ एपीआई और म्यूज़ कोड जैसे उत्पाद शामिल हैं। देसाई की जिम्मेदारी एआई तकनीक को ऐसे उत्पादों और सेवाओं में बदलने की होगी, जिन्हें कंपनियां अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकें। मेटा का यह कदम एआई के क्षेत्र में किए जा रहे बड़े निवेश से कारोबारी सेवाओं के लिए नए अवसर विकसित करने की दिशा में उठाया गया है। मोंगोडीबी ने देसाई के जाने के बाद पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी देव इटिचेरिया को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। देसाई का मेटा में शामिल होना ऐसे समय हुआ है, जब कंपनी एआई मॉडल, एजेंट और तकनीकी ढांचे को कारोबारों के लिए उपलब्ध कराने पर अपना ध्यान बढ़ा रही है।

एस्सार समूह अमेरिका में करेगा 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश

आयोवा में बनेगा अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र, 2030 से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय एस्सार समूह अमेरिका में करीब 18 अरब डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है। इस निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका के आयोवा राज्य में बनने वाले स्टील संयंत्र पर खर्च होगा। करीब 15 अरब डॉलर यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह संयंत्र अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा। इस परियोजना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में की गई। कार्यक्रम में एस्सार समूह के सह-संस्थापक रवि रुइया और उनके बेटे रेवंत रुइया भी मौजूद थे।

स्टील संयंत्र का निर्माण एस्सार समूह की अमेरिकी कंपनी मेसाबी मेटलिक्स करेगी। व्हाइट हाउस के अनुसार, संयंत्र में 2030 तक स्टील का उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तैयार होने के बाद

यहां हर साल करीब एक करोड़ टन स्टील का उत्पादन किया जाएगा। परियोजना से आयोवा में लगभग 1,750 स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। संयंत्र के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एस्सार समूह ने मिनेसोटा में लौह अयस्क की नई खदान भी विकसित की है। इस खदान पर करीब 2.5 अरब डॉलर यानी लगभग 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारी के अनुसार, अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में शुरू होने वाली यह पहली नई लौह अयस्क खदान है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्टील उद्योग फिर से मजबूत हो रहा है। उन्होंने इसका श्रेय स्टील आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क को दिया। ट्रंप के अनुसार, शुल्क से बचने के लिए कंपनियां अमेरिका में ही संयंत्र स्थापित कर रही हैं। एस्सार समूह की शुरुआत 1969 में शशि रुइया और रवि रुइया ने की थी। समूह ऊर्जा, खनन, प्रौद्योगिकी और खुदरा सहित कई क्षेत्रों में कारोबार करता है। भारत में गुजरात के हजीरा में समूह का बड़ा स्टील संयंत्र और वाडिनार में रिफाइनरी है। समूह की ब्रिटेन में स्टैनलो रिफाइनरी और सऊदी अरब में कम कार्बन वाले स्टील संयंत्र की योजना भी है। अमेरिका में मेसाबी मेटलिक्स 2007 से काम कर रही है और मिनेसोटा के नैशवॉक में स्थित है। कंपनी के पास 1.4 अरब टन से अधिक लौह अयस्क संसाधनों का नियंत्रण है।

पापड़मल जी एग्रो फूड्स का आईपीओ लॉन्च, 1 अक्टूबर तक लगा सकते हैं बोली

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: पापड़ और मंगोड़ी जैसे खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी पापड़मल जी एग्रो फूड्स का 20.18 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में एक अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद पांच अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि छह अक्टूबर को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर सात अक्टूबर को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद पहले दिन के अंत तक यह आईपीओ 1.40 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 69 रुपये से लेकर 72 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,600 शेयर का है।

एमएसएमई और सांख्यिकी मंत्रालय के बीच समझौता, व्यवसाय रजिस्टर को नया आधार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बीच सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर के विकास और उसे मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य प्रासंगिक आंकड़ों को साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करना है। इसके तहत एमएसएमई मंत्रालय के पास उपलब्ध उद्यम पंजीकरण से संबंधित इकाईवार आंकड़े एपीआई के माध्यम से साझा किए जाएंगे। इस व्यवस्था से राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर तैयार करने में मदद मिलेगी। समझौता ज्ञापन पर एमएसएमई मंत्रालय के अपर सचिव एवं विकास आयुक्त डॉ. रजनीश और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अपर महानिदेशक डॉ. दलीप सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों मंत्रालयों के बीच उद्यम पंजीकरण प्रणाली से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए एक संरचित प्रारूप विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली व्यावसायिक जानकारी की व्यापकता, एकरूपता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर एक केंद्रीय और नियमित रूप से अद्यतन किया जाने वाला डेटाबेस होता है। इसमें किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी सांख्यिकीय इकाइयों का विवरण दर्ज किया जाता है। इसमें व्यवसाय, उद्यम, प्रतिष्ठान और अन्य आर्थिक इकाइयों के साथ उनकी प्रमुख विशेषताओं तथा आपसी संबंधों की जानकारी शामिल होती है। सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर आर्थिक आंकड़ा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे के रूप में काम करता है। इसके माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए लक्षित आबादी की पहचान, सर्वेक्षण के नमूने का चयन और व्यावसायिक जनसांख्यिकी से जुड़े आंकड़ों के निर्माण में सहायता मिलती है। साथ ही विभिन्न आंकड़ा स्रोतों के बीच एकीकरण और स्थिरता बढ़ाने में भी यह उपयोगी है।

स्पेशल खबर नायरा पंपों पर एक वाहन में अधिकतम 200 लीटर डीजल और 30 लीटर पेट्रोल मिलेगा

कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से रिलायंस-नायरा ने सीमित की पेट्रोल-डीजल बिक्री

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली:

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं होने के कारण निजी ईंधन कंपनियों ने बिक्री सीमित करना शुरू कर दिया है। रिलायंस-बीपी और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री पर नियंत्रण लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 107 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जबकि मई से पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है।

नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर अब एक वाहन में अधिकतम 200 लीटर डीजल और 30 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य उन लोगों पर रोक लगाना है, जो बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। वहीं रिलायंस-बीपी की ओर से बिक्री सीमा को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के पीछे रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में जारी तनाव को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इन परिस्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी आई है। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के लिए घरेलू बाजार में ईंधन बेचने की तुलना में निर्यात करना अधिक लाभदायक हो गया है।

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार, 9 सितंबर तक निजी कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर करीब 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 23 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। कच्चे तेल की कीमतों में और वृद्धि से यह घाटा बढ़ने की संभावना है। इससे पहले रिलायंस-बीपी ने अप्रैल में भी बिक्री पर इसी तरह की पाबंदियां लगाई थीं।

निजी कंपनियों की बिक्री सीमित होने के बाद सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की देश के खुदरा ईंधन बाजार में करीब 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, सरकारी तेल कंपनियां लागत से कम कीमत पर ईंधन बेचने के कारण रोजाना करीब 530 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही हैं। बिक्री सीमा का असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी दिखाई दे रहा है। ट्रक चालकों के अनुसार, कम मात्रा में डीजल मिलने से उन्हें बार-बार पेट्रोल पंपों पर रुकना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं।

ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स का आईपीओ लॉन्च एक अक्टूबर तक लगा सकते हैं बोली

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग के काम में जुटी ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स लिमिटेड का 55.08 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में एक अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद पांच अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि छह अक्टूबर को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर सात अक्टूबर को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद पहले दिन के अंत तक यह आईपीओ 37 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 185 रुपये से लेकर 197 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है।

एआई कंपनी ने कमाए अरबों उर्वशी ने मांगे 7000 करोड़

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की टीम ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्थित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी है। टीम का आरोप है कि कंपनी ने अभिनेत्री की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल अपने कारोबार के लिए किया। इस मामले में उर्वशी की टीम ने करीब 7000 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

उर्वशी की टीम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा कि कंपनी ने उनकी पहचान और डिजिटल सामग्री का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल किया। टीम के अनुसार, इन सामग्रियों के इस्तेमाल से कंपनी ने अरबों डॉलर मूल्य का कारोबार खड़ा किया। हालांकि, टीम ने संबंधित कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। बयान में कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा गया कि वह अपना एआई कारोबार और ब्रांड विकसित कर सकती है, लेकिन उर्वशी के नाम और सामग्री का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सार्वजनिक हस्तियों की तस्वीरों, वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं। उर्वशी की टीम ने भी इसी संदर्भ में उनकी पहचान और सामग्री के कथित अनधिकृत इस्तेमाल पर कानूनी कदम उठाने की बात कही है। हर्जाने की राशि फिलहाल टीम की ओर से 7000 करोड़ रुपये आंकी गई है।